गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 267
दि. 29.01.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

विकास, विश्वास और वैश्विक चुनौतियों के बीच बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मु ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, आज आएगा आर्थिक सर्वेक्षण

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का बुधवार को औपचारिक आगाज हो गया। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक प्रगति का विस्तृत खाका पेश किया। सुबह 11 बजे शुरू हुए अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की नीतियों, सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज एक मजबूत और आत्मविश्वासी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। बीते वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बने हैं। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की प्रगति की रीढ़ होता है और भारत ने इस दिशा में बड़े पैमाने पर निवेश कर भविष्य की नींव मजबूत की है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत आज अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। स्वदेशी तकनीक के दम पर किए गए अंतरिक्ष मिशनों ने न केवल देश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि युवाओं में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति नया उत्साह भी पैदा किया है। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सुधारों से कर प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनी है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला है और राजस्व संग्रह में मजबूती आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्र पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। चार नई सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है, जिससे भारत को इस अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहा विकास रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा कर रहा है और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला रहा है। शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ रुपये के ऐतिहासिक पैकेज का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और निर्यात को बल मिलेगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में आज लगभग दो लाख पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जो नवाचार और उद्यमिता की नई संस्कृति को दर्शाते हैं। सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से लाखों युवाओं को नौकरी मिली है, जिससे बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिली है। साथ ही 20 लाख से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक कौशल से लैस किया गया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे सकें।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सरकार का विशेष फोकस दलितों, गरीबों, आदिवासियों और वंचित वर्गों के उत्थान पर रहा है। 'लखपति दीदी' योजना के तहत बीते एक वर्ष में सात लाख महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, खेल और रक्षा सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं और देश की प्रगति में बराबर की भागीदार बन रही हैं। राष्ट्रपति ने इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया।

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी स्पष्ट शब्दों में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस किया जा रहा है, ताकि वे हर चुनौती का सामना कर सकें। राष्ट्रपति ने कहा कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है और सरकार इस संतुलन को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही देश की आर्थिक दिशा को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी, जो देश की अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करेगा। यह सर्वे बीते वित्त वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन, विकास दर, महंगाई, रोजगार, व्यापार और वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का विश्लेषण करता है और आगामी बजट की नीतिगत दिशा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस बार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय में आ रहा है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से जूझ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, भारत को अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 92 तक पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार के सामने आर्थिक संतुलन बनाए रखने, विकास की रफ्तार को कायम रखने और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026 से आम जनता, उद्योग जगत और निवेशकों को कई अहम उम्मीदें हैं। महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, कर प्रणाली में राहत, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इन सभी पहलुओं की पृष्ठभूमि तैयार करेगा और यह बताएगा कि देश की अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों में मजबूत है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।

कुल मिलाकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। अब आर्थिक सर्वेक्षण और इसके बाद पेश होने वाले आम बजट से यह तय होगा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत अपनी आर्थिक मजबूती और विकास की कहानी को किस दिशा में आगे ले जाता है।

कश्मीर फंडिंग मामले में न्याय की दहलीज पर ठहरी उम्मीद

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सर्द सुबह में जब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, तो अदालत के भीतर सिर्फ कानून की भाषा नहीं गूंज रही थी, बल्कि सात वर्षों से जेल में बंद एक कारोबारी की उम्मीदें भी उस कमरे में मौजूद थीं। कश्मीर घाटी में कथित तौर पर अशांति फैलाने के लिए फंडिंग के आरोपों से घिरे नवल किशोर कपूर की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की सहमति ने इस लंबे और संवेदनशील मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस बहस का हिस्सा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक संतुलन आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं।

यूएई में रहने वाले कारोबारी नवल किशोर कपूर पर आरोप है कि उन्होंने कश्मीर घाटी में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेश से धन मुहैया कराया। इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और जुलाई 2018 में उनकी गिरफ्तारी हुई। तब से अब तक वह सलाखों के पीछे हैं।

सात साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे का अंतिम निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कदम उनके लिए एक बड़ी राहत की किरण की तरह देखा जा रहा है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया है कि वह नवल किशोर कपूर की जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी। यह सहमति अपने आप में अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूएपीए जैसे सख्त कानून के मामलों में शीर्ष अदालत भी बेहद सतर्क रवैया अपनाती है।

कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने अदालत के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आतंक फंडिंग के आरोप ठोस सबूतों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन का मुख्य दावा यह है कि कपूर ने जाहूर अहमद शाह वताली को कुछ धनराशि दी थी, लेकिन उस धन का इस्तेमाल बैंकों के कर्ज चुकाने में हुआ, न कि किसी आतंकी या अलगाववादी गतिविधि में। फरासत ने यह भी जोर दिया कि केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, खासकर तब जब ट्रायल लंबा खिंच रहा हो।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट का मानना था कि पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि कपूर ने विदेश से भारत में धन लाने में भूमिका निभाई, जिसका इस्तेमाल घाटी में हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया गया।

घड़ी की सुई थम गई, महाराष्ट्र की राजनीति एक पल को ठहर गई

(जीएनएस)। राजनीति के गलियारों में शोर बहुत होता है। वहां हर दिन नए नारे गढ़े जाते हैं, रणनीतियां बनती हैं, समीकरण बदलते हैं और सत्ता की बिसात पर लगातार चालें चली जाती हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र की फिज़ा में जो खामोशी है, वह किसी भी नारे, किसी भी भाषण और किसी भी राजनीतिक बयान से कहीं ज्यादा भारी है। यह खामोशी उस सन्नाटे की तरह है, जो किसी विशाल बरगद के अचानक गिर जाने के बाद पूरे जंगल में फैल जाता है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में असमय निधन न सिर्फ एक बड़े नेता का जाना है, बल्कि यह राज्य की राजनीति के एक पूरे युग का अचानक थम जाना है। ऐसा लगता है जैसे समय की रफ्तार कुछ देर के लिए रुक गई हो और सियासत की घड़ी की सुई सचमुच थम गई हो।

अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति की वह धड़कन थे, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चलती रहती थी। लोग उन्हें सत्ता की राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहते थे, लेकिन उनके करीबियों का मानना था कि वह उस नदी की तरह थे, जो अपने लिए रास्ता खुद बनाती है, चाहे उसे कितनी ही चट्टानों को क्यों न काटना पड़े। उनके फैसले तेज होते थे, उनके शब्द सीधे होते थे और उनकी राजनीति में हिचकिचाहट के लिए कोई जगह नहीं थी। आज वही तेज रफ्तार अचानक एक दर्दनाक हादसे में थम गई।

बुधवार की सुबह पुणे जिले के बारामती में हुए इस भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 8:50 बजे, जब अजित पवार चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे, तभी लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया गया कि मुंबई से उड़ान भरने के बाद विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की, लेकिन घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। पहली कोशिश में रनवे स्पष्ट न दिखने पर विमान को दोबारा ऊपर ले जाया गया, लेकिन दूसरी बार लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से पहले ही जमीन से टकरा गया और उसमें आग लग गई। कुछ ही क्षणों में आग ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया और फिर तेज विस्फोटों की आवाज़ों ने आसपास के इलाके को दहला दिया।

इस हादसे में अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी हेड कांस्टेबल विदिप जाधव, मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर, सहायक पायलट कैप्टन सांभवी पाठक और विमान की क्रू सदस्य पिंकी माली की भी जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद विमान में लगातार चार से पांच विस्फोट हुए और आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीमों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीमें मौके पर पहुंचीं। जांच का दायरा अब विमान की तकनीकी स्थिति, मौसम की भूमिका और पायलट के फैसलों तक फैल चुका है। ऑपरेटर कंपनी ने दावा किया है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और पायलट बेहद अनुभवी थे। इसके बावजूद यह सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसने इतने बड़े नेता और उनके साथ मौजूद सभी लोगों की जान ले ली। हादसे से पहले कोई इमरजेंसी कॉल या 'मेडे' सिग्नल न दिया जाना भी जांच का अहम बिंदु माना जा रहा है। अजित पवार के निधन की खबर फैलते ही महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई, पुणे, बारामती और राज्य के अन्य हिस्सों में लोगों की आंखें नम हो गईं। सरकार ने उनके सम्मान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यह फैसला अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अजित पवार का राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कितना बड़ा कद था।

उनका राजनीतिक सफर उतना ही लंबा और जटिल रहा, जितना महाराष्ट्र की राजनीति खुद। अजित पवार छह बार राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में, अलग-अलग गठबंधनों के साथ सत्ता संभाली। कांग्रेस से शुरू होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर अलग रास्ता चुनना और बाद में भाजपा-शिवसेना गठबंधन में शामिल होना—उनकी राजनीतिक यात्रा उतार-चढ़ाव से भरी रही, लेकिन हर मोड़ पर वे चर्चा के केंद्र में रहे। वे ऐसे नेता थे, जो विवादों से घबराते नहीं थे और फैसले लेने में देर नहीं करते थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित देशभर के तमाम नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी ने एक सुर में कहा कि अजित पवार का जाना न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। कई नेताओं ने इस हादसे की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उम्मीद है कि देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वहां मौजूद होंगे। लेकिन इन औपचारिकताओं से परे, जो खालीपन रह जाएगा, वह शायद लंबे समय तक नहीं भर पाएगा। वे एक ऐसे नेता थे, जिनसे लोग सहमत हों या असहमत, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं था।

अंतरजातीय विवाह के विरोध ने ली माता-पिता की जान, बेटी ने ही दिया मौत का इंजेक्शन

(जीएनएस)। विकाराबाद। तेलंगाना के विकाराबाद जिले से मानवता और रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंतरजातीय विवाह का विरोध करने पर एक युवती ने अपने ही माता-पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने 23 वर्षीय युवती को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से नर्स बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक के संपर्क में आई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। कुछ समय बाद युवती ने अपने माता-पिता के सामने शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन युवक के अलग जाति का होने के कारण माता-पिता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। इसी बात से आहत और नाराज होकर युवती ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस के अनुसार, युवती ने अपने माता-पिता को जानलेवा इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने मामले को सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश भी की, लेकिन परिस्थितियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। जांच के दौरान जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवती टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि माता-पिता के लगातार विरोध और दबाव से वह मानसिक रूप से परेशान थी और उसे लगा कि उसके सपनों और फैसलों को कुचल दिया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसी और रिश्तेदार इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक पढ़ी-लिखी युवती, जो दूसरों की जान बचाने के पेशे से जुड़ी थी, वही अपने माता-पिता की जान ले सकती है।

बेजुबानों पर ज़हर का कहर तेलंगाना में इंसानियत हुई शर्मसार

(जीएनएस)। तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले से सामने आई यह खबर किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने के लिए काफी है। तिम्मैपल्ली गांव में एक साथ करीब सौ आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया गया। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पूरी साजिश, योजना और पैसे के दम पर अंजाम दिया गया सामूहिक संहार था। गांव की गलियों में जहां कभी ये बेजुबान जानवर घूमते थे, आज वहां खामोशी है और उस खामोशी में इंसान की क्रूरता की गूंज सुनाई देती है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और पुलिस की शुरुआती जांच से जो तथ्य सामने आए हैं, वे और भी डरावने हैं। बताया गया है कि कुत्तों को मारने के लिए बाहर से विशेष रूप से लोगों को बुलाया गया, जिन्हें 18 हजार रुपये दिए गए। इन लोगों ने एक-एक कर आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन लगाए। मौत के बाद भी संवेदनहीनता यहीं नहीं रुकी। सबूत मिटाने के लिए इन कुत्तों के शवों को गांव से करीब दो किलोमीटर दूर ले जाकर गड्ढों में दफना दिया गया, ताकि किसी को भनक तक न लगे। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब पशु कल्याण कार्यकर्ता एम. प्रीति को गांव में कुत्तों के अचानक गायब होने की जानकारी मिली। जब उन्होंने पड़ताल की, तो ग्रामीणों की फुसफुसाहट और कुछ सुरागों ने इस भयावह सच्चाई की ओर इशारा किया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही चरकोंडा पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। अब तक 12 कुत्तों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी शवों की तलाश जारी है।

पुलिस ने इस मामले में गांव के सरपंच के बेटे, पंचायत सचिव और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इस नृशंस कृत्य के पीछे सत्ता और वादों का दबाव था। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के दौरान ग्रामीणों से यह वादा किया गया था कि गांव को आवारा कुत्तों की समस्या से मुक्त कराया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद नसबंदी, टीकाकरण या पुनर्वास जैसे कानूनी और मानवीय विकल्पों को अपनाने के बजाय, सबसे आसान और अमानवीय रास्ता चुना गया—मौत का रास्ता।

यह घटना सिर्फ तिम्मैपल्ली गांव तक सीमित नहीं है। तेलंगाना में यह एक भयावह ट्रेंड बनता जा रहा है। आधिकारिक और गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर से अब तक राज्य के अलग-अलग जिलों में करीब 1,200 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारा जा चुका है। कहीं खाने में जहर मिलाकर, कहीं इंजेक्शन के जरिए और कहीं अन्य क्रूर तरीकों से इन बेजुबानों को मौत के घाट उतारा गया।

इस सिलसिले ने प्रशासन की भूमिका और पशु कल्याण कानूनों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आना यह दर्शाता है कि कानून या तो कागजों तक सीमित हैं या फिर उन्हें लागू करने की इच्छाशक्ति की भारी कमी है। पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी।

गांवों और कस्बों में आवारा कुत्तों की समस्या एक वास्तविक चुनौती है, लेकिन इसका समाधान हत्या नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट और पशुपालन विभाग बार-बार साफ कर चुके हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास ही एकमात्र कानूनी और मानवीय उपाय हैं। इसके बावजूद, चुनावी वादों और तात्कालिक दबावों में ऐसे क्रूर फैसले लेना समाज को एक खतरनाक दिशा में ले जा रहा है।

तिम्मैपल्ली की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम विकास और व्यवस्था के नाम पर अपनी संवेदनाएं खोते जा रहे हैं। बेजुबान जानवरों पर इस तरह ज़हर का कहर सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि इंसानियत की हार भी है। अब निगाहें प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर हैं कि क्या इस मामले में दोषियों को सख्त सजा मिलेगी या यह घटना भी आंकड़ों और फाइलों में दबकर रह जाएगी।

संपादकीय

खौफनाक पढ़ाई

पिछले दिनों फरीदाबाद में ठीक से पढ़ाई न कर सकने वाली बच्ची की पिता द्वारा पिटाई करने से हुई मौत की खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोरा है। यह विश्वास करना कठिन है, कोई पिता इतना क्रूर हो सकता है कि महज गिनती न सीख पाने के कारण बच्ची की जान ले ले। यदि इस घटना के पीछे कोई परोक्ष कारण नहीं है तो निश्चय ही यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिये कलंक ही कही जाएगी। यह शर्म की बात ही है कि इस ज्ञान की सदी में किसी बच्ची की पिता के हाथों पढ़ाई के नाम पर मौत हो जाए। यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी हमारे समाज में मानसिक ग्रंथि की वह गांठ नहीं खुल पाई है, जो मानती है कि डर व मारपीट से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं आज भी हमारे स्कूलों व घरों तक में सामने आती हैं। यदि स्कूल या कोचिंग में किसी बच्चे-बच्ची के साथ पढ़ाई के नाम पर आक्रामक व्यवहार होता है तो उम्मीद की जाती है कि परिवार उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा होगा। लेकिन जब घर में माता-पिता ही हिंसक व्यवहार करने लगें तो मासूम किसके भरोसे रहेगा... कहने को देश में बच्चों के साथ होने वाले किसी भी हिंसक व्यवहार को रोकने के लिये तमाम तरह के प्रावधान सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब प्रवर्तन एजेंसियां ही उदासीन रहेंगी तो समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। पहले तो स्कूलों में ही ऐसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, फिर यदि मामला पुलिस या संबंधित विभाग के संज्ञान में आता भी है तो उसे रफा-दफा करने के प्रयास तेज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में शिक्षक अभिभावक संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। जिसमें अकसर शिक्षण संस्था के सुर में बोलने वाले अभिभावकों को ही रखा जाता है। आज भी यह एक गंभीर समस्या है और इसके गंभीर समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है।

यह हमारे समाज की विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी यह सोच बलवती है कि बच्चों के साथ सख्त व्यवहार से उनकी पढ़ने-लिखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि हकीकत यह है कि किसी भी आक्रामक व्यवहार से बच्चों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश व दुनिया में हुए तमाम शोध व अध्ययन बताते हैं कि बच्चों के साथ सख्त व आक्रामक व्यवहार किए जाने से बच्चों की एकाग्रता व याद्दाश्त पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जिसका नकारात्मक असर यह होता है कि बच्चे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कालांतर यह भय व कुंठा जीवनभर उनका पीछा करती है। उनका आत्मविश्वास डिग जाता है। तब वे जीवन की स्पर्धा में भी दब्बू बनकर रह जाते हैं। यह भी विडंबना ही है कि आज भी बच्चों पर पढ़ाई का बोझ थोपने से पहले हमारे यहां किसी तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता है कि बच्चे की अभिरुचि किन विषयों में है। सही मायनों में हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कुदरत उसकी रचना किसी खास मकसद के लिये करती है। लेकिन मां-बाप व शिक्षक पहचान नहीं पाते कि उसका रुझान किस दिशा में है। यदि समय रहते बच्चे की उस प्रतिभा को पहचाना जा सके और उस विषय व दिशा में उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो वे अप्रत्याशित रूप से किसी भी क्षेत्र में शिखर की सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कई तरह के जन्मजात व आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जो उनकी सामान्य पढ़ाई में बाधक हो सकता है। कई बच्चों में जन्म से ही दृष्टि दोष या कोई अन्य शारीरिक व मानसिक विकार भी हो सकता है, जिसके चलते वे अपनी पढ़ाई को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। फलतः उन्हें शिक्षकों व परिजनों के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। आज बच्चों को संवेदनशील ढंग से देखने की जरूरत है ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके।

सरल नहीं पर प्रभावशाली थे, आदर्शवादी नहीं पर निर्णायक थे अजित पवार

> अजित पवार ने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए और यहीं से बारामती की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होती गईं। 1991 में वह पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए।

महाराष्ट्र की राजनीति को आज तब गहरा आघात लगा जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद यह दुर्घटना हुई। हादसे की खबर फैलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। देखा जाये तो अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी जमीन से नाता नहीं तोड़ा। वह भले ही कभी मुख्यमंत्री न बने हों, लेकिन राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने का इतिहास उनके नाम दर्ज है। छह बार उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले अजित पवार ने अलग-अलग सरकारों में अपनी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। बारामती में अजित पवार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण उनका काम खुद था। वह उन गिने चुने नेताओं में थे जिनके लिए अपना खुद का चुनाव प्रचार एक औपचारिकता भर था। विधानसभा चुनावों में वह हमेशा समय पर अपना नामांकन दाखिल करते थे, लेकिन उसके बाद बारामती की गलियों में शायद ही कभी उन्हें प्रचार करते देखा गया। जनता जानती थी कि किसे वोट देना है, इसलिए जनता ही उनका प्रचार करती थी। अजित पवार का भरोसा नारों पर नहीं, काम पर था। इसी आत्मविश्वास के चलते वह बारामती से निश्चिंत रहकर राज्य के दूसरे इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट जाते थे। बारामती उनके लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वह उनका कर्मक्षेत्र था, जहां उन्होंने यह साबित किया कि जब विकास बोलता है तो नेता को खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।अजित पवार ने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए और यहीं से बारामती की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होती गईं। 1991 में वह पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने यह सीट शरद पवार के लिए खाली की। इसके बाद वह बारामती से सात बार विधायक बने। उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार और दो पुत्र जय और पार्थ हैं। सहकार से सत्ता तक का उनका सफर बारामती से शुरू हुआ और वहीं समाप्त हुआ।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव आयोग ने पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह सौंपा था। यह गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति के साथ जुड़ा। वहीं उनके चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अलग रह कर एनसीपी-एससीपी का नेतृत्व संभाला। यह विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ माना गया। दोनों पक्षों का विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुँचा लेकिन हाल के दिनों में पवार परिवार एकजुट नजर आ रहा था। हम आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार कर पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों में तीखापन ला दिया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह फैसला एक भूल था। राजनीति के उस कठोर दौर के बाद हालिया निकाय चुनावों में उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वह उनके व्यक्तित्व का दूसरा और अधिक मानवीय पक्ष सामने लाता है। शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर दोनों एनसीपी को एक मंच पर लाने की पहल उन्होंने खुद की थी। बहन सुप्रिया के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि परिवार में कोई मतभेद नहीं हैं और जनता चाहती है कि दोनों दल साथ मिलकर काम करें। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक स्वीकारोक्ति भी थी। देखा जाये तो अपने निधन से पहले अजित पवार कम से कम इतना तो कर ही गए कि उन्होंने परिवार से सुलह कर ली, टूटे रिश्तों को जोड़ दिया और महाराष्ट्र की राजनीति को यह संकेत दे दिया कि टकराव नहीं, संवाद ही आगे का रास्ता है।अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अजित पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। गठबंधनों के बदलते दौर में भी अपनी उपयोगिता और असर बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही। अजित पवार चूंकि केंद्र और महाराष्ट्र में सत्तारुढ़ एनडीए के प्रमुख घटक थे इसलिए उनका निधन बड़ा राजनीतिक नुकसान भी है।

देखा जाये तो अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह उस राजनीतिक शैली का अंत है जो चुपचाप काम करने में यकीन रखती थी। उनकी राजनीति प्रशासनिक पकड़, आंकड़ों की समझ और सत्ता की नस पहचानने की कला से बनी थी। शरद पवार की विशाल छाया में राजनीति शुरू करना आसान था, लेकिन उस छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन था। अजित पवार ने यह कठिन रास्ता चुना। वह हमेशा इस द्वंद्व में रहे कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए या एक स्वतंत्र नेता के रूप में। शायद इसी बेचैनी ने उन्हें बार-बार जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया।

2023 की वह सुबह भारतीय राजनीति के सबसे नाटकीय क्षणों में गिनी जाती है जब उन्होंने अचानक सत्ता का समीकरण बदल दिया था। उनकी काफी आलोचना हुई, अविश्वास भी पैदा हुआ, लेकिन यह भी सच है कि उसी क्षण ने उन्हें निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। बाद में चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में जाना इस बात का संकेत था कि राजनीति में साहस कई बार वैधता भी दिला देता है। अजित पवार की राजनीति नैतिकता के आदर्शों की किताब से कम और यथार्थ की जमीन से ज्यादा निकली थी। यही कारण है कि वह आलोचकों के निशाने पर भी रहे और समर्थकों के भरोसे का केंद्र भी बने। वह जानते थे कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन प्रभाव बनाया जा सकता है। उन्होंने वही किया। विभिन्न लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मैंने खुद देखा कि वह समर्थकों और कार्यकर्ताओं के कितने करीब रहते हैं और सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। यही कारण था कि बारामती में खासतौर पर अजित दादा के नाम का बोलबाला हर जगह देखने को मिलता है।

आज जब उनका जाना अचानक और असमय हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति एक खालीपन महसूस कर रही है। यह खालीपन सिर्फ पद का नहीं, उस अनुभव का है जो दशकों में गढ़ा जाता है। आने वाले समय में यह सवाल और तीखा होगा कि क्या कोई नेता सहकार से सत्ता तक के इस रास्ते को फिर उसी धार और दृढ़ता से तय कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजित पवार की विरासत विरोधाभासों से भरी रही, लेकिन शायद यही उनकी सच्ची पहचान भी है। वह सरल नहीं थे, पर प्रभावशाली थे। वह आदर्शवादी नहीं थे, पर निर्णायक थे। और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

प्रेरणा

भय के बिना सच: एक स्वस्थ समाज की असली पहचान

मनुष्य से गलती होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति है। सोचने-समझने, निर्णय लेने और कर्म करने की प्रक्रिया में त्रुटि आना स्वाभाविक है। इसके बावजूद समाज ने गलती को ऐसा भयावह रूप दे दिया है कि लोग उससे नहीं, बल्कि उसके स्वीकार करने से डरने लगे हैं। यही डर धीरे-धीरे सच को दबा देता है और झूठ को जीवन का हिस्सा बना देता है। प्रसिद्ध दार्शनिक मॉन्तेन से जुड़ी घटना इसी गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सत्य को उजागर करती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।

जब मॉन्तेन अपने बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने उस छोटे नौकर को घबराकर भागते देखा, तो वह दृश्य साधारण लग सकता है। पर उस घबराहट में एक पूरी व्यवस्था की झलक छिपी थी। वह नौकर केवल कांच के टूटे प्याले से नहीं डर रहा था, बल्कि उस सज़ा से डर रहा था जो सच बोलने के बाद मिल सकती थी। उसका भय इस बात का संकेत था कि उसके अनुभवों में गलती का अर्थ सुधार नहीं, बल्कि दंड रहा है। यही मानसिकता समाज में गहराई तक बैठ चुकी है।

मॉन्तेन का व्यवहार इस कहानी को असाधारण बना देता है। उन्होंने नौकर को डांटने के बजाय उसके डर को समझा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि नुकसान कितना हुआ, बल्कि यह पूछा कि वह इतना भयभीत क्यों है। यह प्रश्न अपने आप में मानवीय करुणा और गहरी समझ को दर्शाता है। जब उन्होंने कहा कि "मुझे प्याला नहीं चाहिए, मुझे यह चाहिए कि तुम सच्चाई बोलने में सुरक्षित महसूस करो," तब उन्होंने मूल समस्या पर चोट की। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तु से अधिक मूल्यवान सत्य है और डर से अधिक जरूरी विश्वास। यदि हर गलती पर व्यक्ति को डराया जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी गलती छुपाने लगेगा। यही वह बिंदु है जहां से झूठ जन्म लेता है। झूठ कोई नैसर्गिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि भय की उपज है। व्यक्ति सच बोलना चाहता है, लेकिन परिणामों का डर उसे रोक देता है। धीरे-धीरे वह झूठ बोलने में सहज हो जाता है और अंततः सच से उसका संबंध कमजोर पड़ जाता है। मॉन्तेन का कथन कि "जहां सच बोलने पर सज़ा मिलती है, वहां झूठ पनपता है" मानव मनोविज्ञान की इस सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में व्यक्त करता है। इस घटना का प्रभाव केवल उस एक नौकर तक सीमित नहीं रहा। पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। लोग गलती होने पर उसे छुपाने के बजाय सामने लाने लगे। इससे दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला, समस्याएं समय रहते पकड़ में आने लगीं और दूसरा, हर गलती सीख का माध्यम बन गई। जब डर नहीं होता, तो व्यक्ति जिम्मेदारी से अपनी भूल स्वीकार करता है और उसे सुधारने का प्रयास भी करता है। यही प्रक्रिया किसी भी स्वस्थ परिवार, संगठन या समाज की पहचान होती है।

आज के समय में इस विचार की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। घरों में माता-पिता अक्सर बच्चों को गलती पर डांट देते हैं, जिससे बच्चा सीखने के बजाय बचने की कोशिश करने लगता है। स्कूलों में छात्र अंक और सज़ा के डर से नकल करते हैं। कार्यालयों में कर्मचारी अपनी गलती छुपाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर करते हैं। शासन और प्रशासन में भी सच सामने लाने वाले लोग अक्सर दंडित होते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले सुरक्षित रहते हैं। ऐसे माहौल में ईमानदारी एक जोखिम बन जाती है।

गलती और व्यक्ति के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। गलती एक क्रिया है, पहचान नहीं। जब हम व्यक्ति को उसकी गलती से जोड़ देते हैं, तो हम उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इससे व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है और सच बोलने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। मॉन्तेन ने इस अंतर को समझा और इसी कारण वे नौकर के लिए शिक्षक बन गए, केवल मालिक नहीं। डरमुक्त वातावरण केवल सहानुभूति से नहीं, बल्कि स्पष्टता से भी बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलती पर कोई सीख या जिम्मेदारी न हो। इसका अर्थ यह है कि सुधार का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि समझ होना चाहिए। जब व्यक्ति जानता है कि गलती स्वीकार करने पर उसे अपमान नहीं, बल्कि मार्गदर्शन मिलेगा, तो वह सच बोलने में संकोच नहीं करता।

इतिहास गवाह है कि जिन समाजों और संस्थानों में आत्मालोचना और सच बोलने की संस्कृति रही है, वे आगे बढ़े हैं। विज्ञान में खोजें गलत प्रयोगों से ही संभव हुई हैं। लोकतंत्र में सुधार आलोचना से ही आता है। व्यक्तिगत जीवन में परिपक्वता अपनी भूल स्वीकार करने से ही विकसित होती है। इसके विपरीत, जहां गलती स्वीकार करना कमजोरी समझा गया, वहां पतन अवश्यंभावी रहा है।

मॉन्तेन की यह छोटी-सी कहानी हमें बड़ा प्रश्न देती है—हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? ऐसा समाज जहां लोग निर्दोष दिखने के लिए झूठ बोलें, या ऐसा समाज जहां लोग ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर बेहतर बन सकें? कांच का प्याला टूटना एक मामूली घटना थी, लेकिन उस पर दी गई प्रतिक्रिया ने यह सिखा दिया कि सच्चाई की रक्षा कैसे की जाती है।

अंततः सच बोलने का साहस तभी जन्म लेता है जब उसे सुनने वाला भय नहीं, समझ रखता हो। जब नेतृत्व, परिवार और समाज इस समझ को अपनाते हैं, तभी झूठ की जड़ें कमजोर होती हैं। मॉन्तेन का दृष्टिकोण हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा अनुशासन डर से नहीं, विश्वास से पैदा होता है, और यही विश्वास किसी भी सभ्य समाज की सबसे मजबूत नींव होता है।

कनाडा के प्रधानमंत्री की स्वदेशी अपनाने की अपील का संदेश

कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी को देखते हुए ये अपील की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो वह कनाड़ा पर सौ फीसदी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एक वीडियो संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव है। ऐसे में कनाडा के लोगों के पास यही रास्ता है कि वो ही सामान खरीदें, जो कनाडा में बने हों। दूसरे देश क्या करते हैं, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में है उसपर फोकस करें। हम ही कनाडा के सबसे अच्छे ग्राहक हैं और हमें कनाडा में बने उत्पाद खरीदने चाहिए ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बीच ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद तल्खी तब और बढ़ गई जब ट्रंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही, हालांकि पिछले साल कार्नी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कनाडा बिकाऊ नहीं है। आज जो हालात कनाडा के साथ हैं, वही दुनिया के कई अन्य देशों के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी भारत तो धमकी देते हैं तो कभी चीन को। ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले देशों को भी इस तरह की उनकी हाल में धमकी आई है। इस तरह की धमकी एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। बड़ी शक्तियों छोटी शक्ति और देशों को दबाकर रखना चाहती हैं। वे छोटे और सम्प्रभू देशों को अपना गुलाम बनाकर रखना पसंद करती है। अपने पर निर्भर बनाए रखना चाहती है। इस तरह के आसन्न खतरे को भारत ने पहले ही भांप लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी समय से स्वदेशी अपनाने पर वैसे ही नही जोर दे रहे। भारत में स्वदेशी का विचार कोई नया नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नया आयाम दिया है। वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए उन्होंने देशवासियों से भारतीय उत्पादों को अपनाने और उन्हें वैश्विक बनाने का आह्वान किया है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। उनका हम पर दबाव कम होगा। स्वदेशी की अवधारणा को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को याद करना होगा। गांधीजी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक रणनीति के रूप में नहीं देखा था, बल्कि इसे स्वराज और आत्मनिर्भरता के व्यापक दर्शन का हिस्सा माना था। उनका मानना था कि जब तक हम आर्थिक रूप से परतंत्र रहेंगे, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और चरखे से बने खादी को अपनाने पर जोर दिया। गांधीजी के लिए चरखा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, बल्कि यह आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक था। दरअसल अंग्रेजों के शासन से पहले जरूरत का सारा सामान हमारे यहां गांव–गांव और आसपास में पैदा होता हैं। जरूरत का काफी सामान हम अपने घर तैयार कर लेते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बड़ेबड़े उद्योग लगाकर खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का महत्व समझा। उनका स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार बना। उन्होंने लोगों को समझाया कि जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने देश की संपत्ति को बाहर भेज रहे हैं, बल्कि अपने कारीगरों और श्रमिकों को भी बेरोजगार कर रहे हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक भारतीय को अपने गांव और अपने देश में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विचार इतना प्रभावशाली था कि लाखों भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी को अपनाया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि इसने राष्ट्रीय चेतना को जगाने और लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की वैश्वीकृत दुनिया में स्वदेशी की अवधारणा नए अर्थ और महत्व प्राप्त कर रही है। कनाडा पर ट्रंप की टैरिफ धमकी यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना अनिश्चित और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है, तो व्यापार शुल्क एक प्रमुख हथियार बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो देश अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत रखते हैं, वे बेहतर तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से देश में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया है। भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल इसी दिशा में एक व्यापक और दूरदर्शी कदम है। इस अभियान का उद्देश्य केवल आयात को कम करना नहीं है, बल्कि भारत को विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्मकेंद्रित होना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार बनना है। जब भारतीय उत्पाद गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्ट होंगे, तो वे न केवल घरेलू बाजार में सफल होंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाएंगे।

अभियान

हनुमान कृपा के रहस्यमय उपाय: गुप्त भक्ति से कैसे बदलता है भाग्य और टूटते हैं संकट

सनातन परंपरा में हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि साहस, सेवा, संयम और संपूर्ण समर्पण के जीवंत प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें संकटमोचन कहा गया है, क्योंकि वे न केवल बाहरी बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर बसे भय, आलस्य, भ्रम और नकारात्मकता को भी नष्ट करते हैं। कलियुग में हनुमान जी की उपासना इसलिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सच्चे भाव से की गई भक्ति का तुरंत फल देते हैं। शास्त्रों और लोकमान्यताओं में यह बात बार-बार कही गई है कि हनुमान जी को दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि गुप्त और निस्वार्थ भक्ति अत्यंत प्रिय है।

गुप्त भक्ति का अर्थ है ऐसी आराधना जिसमें अहंकार, प्रदर्शन और प्रशंसा की इच्छा न हो। जब भक्त बिना किसी को बताए, बिना किसी अपेक्षा के, केवल श्रद्धा और विश्वास से कुछ अर्पित करता है, तब वह सीधा हनुमान जी के हृदय तक पहुंचता है। यही कारण है कि गुप्त दान और गुप्त सेवा को हनुमान उपासना में विशेष स्थान दिया गया है। यह भक्ति साधक के भीतर के दोषों को जलाकर उसे भीतर से मजबूत बनाती है। ऐसे ही कुछ रहस्यमय उपाय हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रीय मान्यताओं और लोक अनुभवों में मिलता है, और जिनका गुप्त रूप से पालन करने पर जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः दूर होने लगती हैं।

पूजा-पाठ में लौंग को अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना गया है। लौंग में अग्नि तत्व और शुद्धिकरण की शक्ति मानी जाती है। जब कोई भक्त मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बिना किसी को बताए एक या दो साबुत लौंग उनके चरणों में रख देता है, तो यह छोटा-सा कार्य बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और वातावरण को सकारात्मक बनाती है। लौंग अर्पित करने वाला भक्त अपने जीवन से भय, मानसिक तनाव और अदृश्य बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है, जिनके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या जिन्हें बिना कारण मानसिक अशांति बनी रहती है। गुप्त रूप से किया गया यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और सौभाग्य को आकर्षित करता है।

माचिस को सामान्य जीवन में एक छोटी-सी वस्तु माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अग्नि तत्व का सशक्त प्रतीक है। हनुमान जी को अग्नि से विशेष संबंध है, क्योंकि उनके जीवन में अग्नि तत्व शक्ति, तेज और शुद्धि का माध्यम रहा है। जब कोई भक्त हनुमान जी को गुप्त रूप से माचिस अर्पित करता है, तो इसका अर्थ केवल एक वस्तु देना नहीं होता, बल्कि यह प्रार्थना होती है कि मेरे भीतर की कमजोरी, डर, आलस्य और नकारात्मक विचार जलकर भस्म हो जाएं। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है, जो निर्णय लेने में कमजोर महसूस करते हैं या जिनके भीतर ऊर्जा की कमी रहती है। माचिस का गुप्त दान जीवन में नया प्रकाश लाने वाला माना गया है, जिससे व्यक्ति अंधकार से बाहर निकलकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है।

तुलसी को सनातन धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु और उनके अवतार श्रीराम को तुलसी अत्यंत प्रिय है, और हनुमान जी तो स्वयं श्रीराम के अनन्य भक्त हैं। ऐसे में जब कोई भक्त हनुमान जी के चरणों में गुप्त रूप से तुलसी की कुछ पत्तियां अर्पित करता है, तो यह भक्ति सीधे राम कृपा से जुड़ जाती है। तुलसी शुद्धता, सात्त्विकता और रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। गुप्त रूप से तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति की भक्ति निर्मल होती है और उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। यह उपाय स्वास्थ्य, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी की उपस्थिति वातावरण को पवित्र करती है और साधक के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाती है।

हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका राम नाम में अटूट विश्वास है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी स्वयं राम नाम के जप से संचालित होते हैं। इसलिए किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक प्रभावशाली उपाय है गुप्त रूप से राम नाम का जाप। जब भक्त मंदिर में या घर में हनुमान जी के सामने बैठकर मन ही मन "राम" नाम का जप करता है, बिना किसी को दिखाए, बिना ऊंचे स्वर में, तब वह सीधे हनुमान जी की चेतना से जुड़ जाता है। यह गुप्त नाम जाप साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गुप्त रूप से राम नाम का स्मरण करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय, शत्रु बाधा या मानसिक अशांति स्पर्श नहीं कर पाती। यह उपाय आत्मिक बल को बढ़ाता है और व्यक्ति को भीतर से स्थिर और निर्भीक बनाता है।

पीले रंग को ज्ञान, शुभता और गुरु तत्व का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष में पीला रंग गुरु ग्रह से जुड़ा होता है, जो बुद्धि, विवेक और धर्म का कारक है। हनुमान जी को गुप्त रूप से पीला वस्त्र अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में विवेक और समझ का विकास होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है, जिनके जीवन में बार-बार पारिवारिक कलह, आर्थिक तनाव या निर्णय संबंधी भ्रम बना रहता है। पीला वस्त्र चुपचाप हनुमान जी के मंदिर में रख देना चाहिए, बिना किसी दिखावे के। ऐसा करने से धन-संपत्ति, मान-सम्मान और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। यह उपाय गुरु कृपा को भी मजबूत करता है, जिससे जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है।

इन सभी उपायों का मूल भाव एक ही है—निस्वार्थता और गुप्त भक्ति। हनुमान जी को वह भक्ति प्रिय नहीं जिसमें अहंकार या प्रदर्शन हो, बल्कि वह भक्ति प्रिय है जिसमें साधक स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है। जब भक्त बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल श्रद्धा से कुछ अर्पित करता है, तब हनुमान जी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। ऐसे उपाय जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होते हैं।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि हनुमान जी की कृपा केवल संकट दूर करने तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वह संकटों से डरना ही छोड़ देता है। गुप्त भक्ति व्यक्ति के चरित्र, सोच और कर्मों को शुद्ध करती है। जब भीतर शुद्धता आती है, तो बाहर के संकट स्वतः कमजोर पड़ जाते हैं। यही बजरंगबली की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली कृपा मानी जाती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

विमान हादसे में जौनपुर की बेटी पिंकी माली का निधन, गांव भैसा से मुंबई तक पसरा मातम

(जीएनएस)। जौनपुर। देश की एविएशन दुनिया से जुड़ी एक दुखद खबर ने पूर्वांचल से लेकर मुंबई तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक विशेष विमान यात्रा के दौरान हुए हादसे में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की 29 वर्षीय युवती पिंकी माली की मौत हो गई। पिंकी उस विमान में केबिन क्रू के रूप में तैनात थीं, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक अहम यात्रा हो रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही केराकत तहसील क्षेत्र के उनके पैतृक गांव भैसा में शोक की लहर दौड़ गई। गांव की गलियों से लेकर घरों के आंगन तक मातमी सन्नाटा छा गया और हर आंख नम दिखाई दी।

भैसा गांव जिला मुख्यालय से लगभग पचास किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे ही टेलीविजन चैनलों और मोबाइल फोन के जरिए यह खबर गांव तक पहुंची कि विमान हादसे में पिंकी माली की जान चली गई है, लोग अविश्वास और पीड़ा के बीच उनके घर की ओर दौड़ पड़े। मां-बाप, रिश्तेदार और पड़ोसी किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि गांव की वह होनहार बेटी, जिसने अपने परिश्रम से आसमान में उड़ने का सपना पूरा किया था, अब कभी लौटकर नहीं आएगी। गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी पिंकी को याद करते हुए भावुक हो उठे।

पिंकी माली का जीवन संघर्ष और सपनों की मिसाल रहा है। सामान्य परिवार में जन्मी पिंकी ने पढ़ाई के साथ-साथ अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखे थे। एविएशन सेक्टर में काम करना उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सपना था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन से साकार किया। चयन के बाद जब वह केबिन क्रू बनीं तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग गर्व से कहते थे कि भैसा गांव की बेटी अब देश-दुनिया के बड़े शहरों और हवाई रास्तों में अपनी पहचान बना रही है। परिवार के लोगों के अनुसार, पिंकी अपने काम को लेकर बेहद जिम्मेदार और उत्साही थीं। वह अक्सर अपने अनुभव साझा करती थीं और कहती थीं कि यह पेशा उन्हें नई दुनिया देखने और लोगों की सेवा करने का अवसर देता है। हादसे वाले दिन भी उन्होंने घर पर फोन कर अपनी ड्यूटी के बारे में बताया था। परिवार को क्या पता था कि वही बातचीत उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी। इसके बाद संपर्क टूट गया और कुछ ही घंटों में वह मनहूस खबर आ गई, जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी।

पिंकी के पिता शिवकुमार माली महाराष्ट्र में रहकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उनका गांव से गहरा भावनात्मक रिश्ता बना रहा। ग्रामीणों के अनुसार, वह हर वर्ष दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाते थे और गांव आकर लोगों से मिलते-जुलते थे। शिवकुमार माली ने वर्षों पहले रोज़गार की तलाश में मुंबई का रुख किया था और अपने परिश्रम से परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दिया। पिंकी की सफलता उनके संघर्ष का ही परिणाम मानी जाती थी। आज वही पिता अपनी बेटी को खो देने के गहरे सदमे में हैं।

पिंकी के निधन की खबर फैलते ही माली समाज में भी शोक की लहर दौड़ गई। समाज के लोगों ने इसे केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की क्षति बताया। लोगों का कहना है कि पिंकी जैसी बेटियां समाज के लिए प्रेरणा होती हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखती हैं। गांव के लोग पिंकी की सादगी, व्यवहार और मेहनत को याद कर भावुक हो रहे हैं।

हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार यह एक विशेष यात्रा के दौरान हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, जिसमें विमान में मौजूद क्रू और यात्रियों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। वहीं, पिंकी के पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक पहुंचाने और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर भी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। गांव में लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले।

जौनपुर जनपद में इस घटना को लेकर शोक और संवेदना का माहौल बना हुआ है। सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि पिंकी ने अपने छोटे से गांव से निकलकर जो पहचान बनाई, वह हमेशा याद रखी जाएगी। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनके सपने और उनकी उड़ान की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

जुल्म, खामोशी और एक खौफनाक फैसला: सूरत में पति की हत्या ने खोले रिश्तों के काले सच

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को झकझोर दिया है, बल्कि समाज में छिपे घरेलू अत्याचार और वैवाहिक हिंसा के भयावह सच को भी उजागर कर दिया है। यहां 37 वर्षीय एक महिला को अपने ही पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को अंदर तक हिला देने वाले हैं। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि उस लंबे दर्द, प्रताड़ना और मजबूरी की कहानी है, जो एक महिला वर्षों तक सहती रही और अंत में एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला और उसका पति मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले थे। रोज़गार की तलाश में पति मुंबई में मजदूरी करता था और महीने में कभी-कभार सूरत आता था, जहां पत्नी रहती थी। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य दंपती का जीवन लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे महिला की जिंदगी एक डरावने सपने से कम नहीं थी। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति ताकत बढ़ाने वाली गोलियों और दवाओं का सेवन करता था और उनके असर में उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान वह न सिर्फ बेरहमी से पेश आता, बल्कि कई बार उसे गंभीर रूप से घायल भी कर देता था।

महिला के अनुसार, यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। पति के अत्याचार केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी उसे तोड़ चुके थे। यौन उत्पीड़न के कारण कई बार उसे गंभीर चोटें आईं, यहां तक कि रक्तस्राव जैसी स्थिति भी बन जाती थी। उसने कई बार इस यातना का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे डराया-धमकाया गया। समाज, बदनामी और अकेलेपन के डर से वह किसी से खुलकर कुछ कह नहीं पाई। धीरे-धीरे उसके भीतर गुस्सा, भय और बेबसी जमा होती गई, जिसने अंततः उसे एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कीमत अब वह कानून के सामने चुका रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, महिला ने पति से छुटकारा पाने के लिए पहले भी प्रयास किए थे। 1 जनवरी की रात उसने हल्दी वाले दूध में चूहे मारने की दवा मिलाकर पति को पिला दी। उस समय उसकी मंशा साफ थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पति की जान नहीं गई। हालांकि, जहर का असर उसकी सेहत पर पड़ चुका था और वह कमजोर हो गया था। इसके कुछ दिन बाद, 5 जनवरी को जब पति की हालत पहले से ही खराब थी और वह घर पर मौजूद था, तब दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ। उसी रात, महिला ने पति को काबू में किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद महिला ने पूरे मामले को बीमारी से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की।

पश्चिम रेलवे चलाएगी साबरमती-बीकानेर और पोरबंदर-जोधपुर के बीच वन-वे स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-बीकानेर और पोरबंदर-जोधपुर के बीच विशेष किराये पर दो वन-वे स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09491 साबरमती–बीकानेर वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09491 साबरमती–बीकानेर वनवे स्पेशल शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को साबरमती से 17.50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06.30 बजे बीकानेर पहुंचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़, जोधपुर एवं नागौर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और

जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09291 पोरबंदर-जोधपुर वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09291 पोरबंदर-जोधपुर स्पेशल रविवार, 01 फरवरी 2026 को पोरबंदर से 19.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.00 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में वांसजालिया, लालपुर जाम, जामनगर, हापा, राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, पाटन, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल एवं समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09491 और 09291 की बुकिंग 29 जनवरी,2026 सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

असारवा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास तेज़ी से प्रगति पर असारवा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प: व्यापक आधुनिकीकरण एवं यात्री सुविधाओं का विकास

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद क्षेत्र के असारवा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत तीव्र गति से किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म तथा यात्री सुविधाओं का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आधुनिक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत स्टेशन भवन का नवीनीकरण, प्लेटफॉर्म शेड का निर्माण, प्लेटफॉर्म रिसर्फेसिंग तथा पार्किंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न कार्य प्रगति पर हैः प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगभग 34,000 वर्गफुट तथा प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर लगभग 50,000 वर्गफुट क्षेत्रफल में कवर शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को धूप, वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा मिलेगी।

40 फीट चौड़े एवं 82 फीट लंबे फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया को प्लेटफॉर्म संख्या 1 को प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 से जोड़ने के लिए 40 फीट चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की आवाजाही सुगम, सुरक्षित एवं सुचारु होगी। आधा एकड़ के करीब विशाल पार्किंग विकसित की गई है, जिसमें दोपहिया, चारपहिया एवं ऑटो रिक्शा के लिए पृथक एवं सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया गया है, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार होगा। इस योजना के अंतर्गत 20 फीट चौड़ा भव्य प्रवेश एवं निकास द्वार, लगभग 6500 वर्गफुट क्षेत्रफल की कैनोपी सहित डेडिकेटेड पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ जोन तथा सुव्यवस्थित सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में आकर्षक लैंडस्केपिंग एवं विशाल कॉन्कोर्स क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक एवं आरामदायक वातावरण प्राप्त होगा। स्टेशन फसाड़ एवं प्रवेश द्वार का आकर्षक सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे स्टेशन को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय पहचान प्राप्त होगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु डीलक्स ए.सी., नॉन-ए.सी. एवं सामान्य प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, आधुनिक टिकटिंग काउंटर, डिजिटल सूचना प्रणाली, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्तमान में असारवा स्टेशन पर 12 नियमित एवं 4 विशेष ट्रेनों का ठहराव है तथा प्रतिदिन लगभग 10,600 यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 1,00,000 यात्रियों की सुविधा के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहा यह पुनर्विकास न केवल यात्री सुविधाओं में गुणात्मक सुधार लाएगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन एवं रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। पुनर्विकसित असारवा रेलवे स्टेशन आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ अहमदाबाद क्षेत्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा 01 फ़रवरी, 2026 से और चार उपनगरीय ट्रेन सेवाओं की शुरुआत

पश्चिम रेलवे पर कुल सेवाओं की संख्या 1410 हो जाएगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधा बढ़ाने और उपनगरीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 01 फ़रवरी 2026 से 12-कोच वाली 04 अतिरिक्त नॉन-एसी उपनगरीय ट्रेन सेवाएँ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन अतिरिक्त सेवाओं के शुरू होने से पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय खंड पर कुल उपनगरीय सेवाओं की संख्या 1406 से बढ़कर 1410 हो जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि कांदिवली–बोरीवली के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के बाद संभव हो पाई है। छठी लाइन के कमीशन होने के पश्चात बोरीवली और बांद्रा टर्मिनस के बीच सभी बांद्रा टर्मिनस की ओर आने/जाने वाली लम्बी दूरी की ट्रेनों को पाँचवीं एवं छठी लाइन पर स्थानांतरित किया गया है, जिससे परिचालन दक्षता में

उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इन 04 नई सेवाओं में से 02 अप दिशा में और 02 डाउन दिशा में होंगी, जो स्लो मोड में परिचालित की जाएंगी। अप दिशा में एक सेवा भायंदर से बांद्रा के लिए होगी, जो 11:39 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि दूसरी सेवा भायंदर से चर्चगेट के लिए होगी, जो 12:14 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार, डाउन दिशा में 02 अतिरिक्त सेवाएँ बांद्रा से भायंदर के लिए होंगी, जो बांद्रा से क्रमशः 04:30 बजे और 13:21 बजे प्रस्थान करेंगी।

इन सेवाओं के शामिल होने के परिणामस्वरूप कुछ मौजूदा उपनगरीय सेवाओं के समय में मामूली परिवर्तन किए गए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे कृपया इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर यात्रा करें।

पंजाब की AAP सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मानजी का अहमदाबाद में आगमन

- **गुजरात में AAP का संगठन मजबूत, गांव-गांव और शहरों में बड़ी-बड़ी सभाएं हो रही हैं: भगवंत मान**
- **विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया की जीत एक बड़ा संकेत: भगवंत मान**
- **अरविंद केजरीवालजी का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, जिसे पंजाब में भी लागू किया गया है, उसे गुजरात में भी लागू करेंगे: भगवंत मान**
- **SIR की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को सामने आकर संतोषजनक कदम उठाने चाहिए: भगवंत मान**
- **SIR द्वारा यदि नकली जनता बनाई जाती रही तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा?: भगवंत मान**
- **UGC मुद्दे पर यदि कोई सवाल उठ रहे हैं तो उस पर संतोषजनक निरीक्षण होना चाहिए: भगवंत मान**
- **पंजाब ने सबसे अधिक बलिदान दिए हैं और अनाज की कमी के समय ग्रीन रिवोल्यूशन में भी पंजाब का बड़ा योगदान रहा, फिर भी आज तक पंजाब के पास अपनी राजधानी नहीं है: भगवंत मान**
- **महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवारजी की आत्मा को भगवान शांति दे: भगवंत मान**

(जीएनएस)। अहमदाबाद/गुजरात। पंजाब की AAP सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मानजी का आज शाम अहमदाबाद में आगमन हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, विधायक गोपाल इटालिया, विधायक चैतर वसावा, प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता डॉ. करन बारोट सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार का एक गंभीर दुर्घटना में निधन हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वर्तमान में गुजरात में हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत रूप से खड़ा हुआ है। गांव-गांव जनसभाएं हो रही हैं और बड़े शहरों में भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात की जनता अब बदलाव चाहती है। अब तक जो माहौल हमने देखा है, उससे स्पष्ट होता है कि गुजराती जनता कुछ नया चाहती है। कांग्रेस तो यहां लगभग नजर ही नहीं आती। विसावदर से गोपाल इटालिया की शानदार जीत और वह भी बड़े मार्जिन से, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है और हम और अधिक मेहनत के साथ काम करेंगे। अरविंद केजरीवालजी का स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मॉडल है, उसे हमने दिल्ली और पंजाब में सफलतापूर्वक लागू किया है, उसी तरह गुजरात में भी घर-घर तक पहुंचाएंगे।

SIR मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी, किसी भी प्रकार की आपत्ति या शंका हो, तो चुनाव आयोग को स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव आयोग को "72 घंटे में माफी मांगो" जैसी शर्तें नहीं रखनी चाहिए या दबावपूर्ण निर्देश नहीं देने चाहिए, बल्कि पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से पूरी प्रक्रिया की जनता के सामने संतोषजनक जांच करनी चाहिए। यदि SIR द्वारा नकली जनता बनाई जाती रही तो फिर लोकतंत्र

कैसे बचेगा? यह तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। UGC मुद्दे पर उन्होंने कहा कि UGC बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी भी मुद्दे पर यदि किसी को आपत्ति हो—चाहे वह शैक्षणिक संस्थाएं हों, चुनाव आयोग हो या कोई अन्य संवैधानिक संस्था—तो स्पष्टीकरण देना और संतोष प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब यदि पंजाब की बात करें तो देश के लिए सबसे अधिक बलिदान देने वाले राज्यों में पंजाब अग्रणी रहा है। जब देश को अनाज की जरूरत पड़ी, तब पंजाब के किसानों ने ग्रीन रिवोल्यूशन कर अनाज के भंडार भर दिए। फिर भी आज तक पंजाब की अपनी राजधानी नहीं है। चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, वास्तव में पंजाब का अधिकार बनता है। यह मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। पंजाब के पास अपनी अलग हाईकोर्ट नहीं है। जबकि नॉर्थ-ईस्ट के छोटे-छोटे राज्यों के पास भी अपनी हाईकोर्ट है। इस कारण मामलों की पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और व्यवस्था पर भारी बोझ है। आज के समय में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी अपनी राजधानी न हो। चंडीगढ़ पंजाब की ही राजधानी है और पंजाब की ही राजधानी होनी चाहिए।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस और जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 09706/09705 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09706 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09705 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09706 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मजबूत बिक्री और बेहतर परिचालन के दम पर मारुति सुजुकी की कमाई में इजाफा, तीसरी तिमाही में मुनाफा 4 प्रतिशत बढ़ा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजों से एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बदलते बाजार हालात और चुनौतियों के बावजूद कंपनी अपनी पकड़ बनाए हुए है। 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,879 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बीते वर्ष इसी तिमाही में कंपनी ने 3,727 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। मुनाफे में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है, जब ऑटो सेक्टर बढ़ती लागत, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता मांग में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। कंपनी के अनुसार, इस तिमाही में परिचालन स्तर पर उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा। यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात में भी स्थिरता देखने को मिली, जिसका सीधा असर राजस्व पर पड़ा। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी का कुल राजस्व बढ़कर 49,904 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 38,764 करोड़ रुपये था।

"मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" यात्री जागरूकता अभियान का DRM ने किया शुभारंभ

(जीएनएस)। यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने, वैध टिकटिंग को प्रोत्साहित करने तथा रेल यात्रा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को सशक्त करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा जनजागरूकता अभियान "मेरा टिकट, मेरी शान – विकसित भारत के लिए मेरा योगदान" शुरू किया गया। इस अभियान का उद्घाटन वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में किया गया। यह अभियान 28 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वडोदरा स्टेशन पर इस अभियान की शुरुआत करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने यात्रियों से आव्हान किया कि वे टिकट लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएँ, और देश की प्रगति का हिस्सा बने और जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए बताया कि भारत देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा

कर्त्तव्य है कि हम जब भी यात्रा करें, टिकट लेकर यात्रा करें, टिकट लेना गर्व की बात है, हमारी शान है। आपके इस योगदान से न सिर्फ देश का विकास होता है बल्कि रेलतंत्र भी मजबूत होता है। रेलगाड़ियाँ मॉडर्न और सुरक्षित होती है और रेल नेटवर्क के साथ साथ रेल सुविधाओं ने उन्नयन और सुधार भी होता है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने मीडिया को आगे बताया कि वडोदरा मंडल पर लगभग 1.4 लाख यात्री प्रतिदिन रेल से सफ़र करते है। मंडल पर यात्रियों में डिजिटल माध्यमों से अपना अनारक्षित टिकट बुक करने में पिछले वर्ष के मुकाबले 35 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटलाइजेशन के विज़न तथा 'डिजिटल इंडिया' पहल के प्रति यात्रियों के बढ़ते विश्वास और सहभागिता को दर्शाती है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारतीय रेल का RailOne ऐप यात्रिओं के लिए सुविधाओं के बारे में ऑल इन वन मोबाइल ऐप है। इसके बारे में भी लोगों को इस अभियान के अंतर्गत जागरूक किया जाएगा। RailOne एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्थिति, PNR जानकारी, भोजन सेवा तथा यात्री सहायता जैसी अनेक सेवाओं का एक ही स्थान पर लाभ उठा सकते हैं।

वडोदरा के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह अभियान 28 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वडोदरा मंडल के अंतर्गत यह अभियान वडोदरा, आनंद, एकतानगर एवं भरुच स्टेशनों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत स्टेशन तथा विभिन्न डिजिटल व जनसंचार माध्यमों द्वारा व्यापक जनसंपर्क गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

दिल्ली से पहाड़ों तक मौसम का बदला मिजाज, बारिश–बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, जनजीवन पर असर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हिमालयी राज्यों तक सर्दी, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। जनवरी के आखिरी दिनों में मौसम का यह बदला हुआ रूप लोगों की दिनचर्या पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। दिल्ली में जहां बीते चार वर्षों की तुलना में इस बार जनवरी में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दिल्ली में मंगलवार को गरज के साथ हुई बारिश ने ठंड का अहसास और बढ़ा दिया। इस बार जनवरी महीने में राजधानी में अब तक 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से कहीं अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्का कोहरा छाने के आसार हैं, जबकि दोपहर बाद कुछ देर के लिए धूप निकल सकती है। हालांकि, ठंड से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संकेत दिया है कि 28 से 31 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक फरवरी को एक बार फिर राजधानी में तेज बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए एक फरवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी मौसम का असर साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 28 जनवरी को गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। यहां हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार में तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। सिक्किम के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 30 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से एक और दो फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। इससे ठंड का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। कोहरे और शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। 28 से 30 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 28 से 31 जनवरी के दौरान शीतलहर की स्थिति बनने के आसार हैं, जबकि हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में ठंडे दिन की चेतावनी भी दी गई है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी ने हालात और कठिन बना दिए हैं। हिमाचल के कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को गोंदला में 22 सेंटीमीटर, कुकुमसेरी में 21.3 सेंटीमीटर और कोठी में 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। ताबो प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान शून्य से नीचे गिरकर माइनस 8.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

जम्मू-कश्मीर में भी भारी हिमपात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खराब मौसम के चलते श्रीनगर हवाई अड्डे से 58 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यातायात ठप हो गया है और कई इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है।

डिजी मुद्रा घोटाले में बड़ा शिकंजा, जयपुर से कंपनी निदेशक प्रकाश जैन गिरफ्तार, हजारों निवेशकों से ठगी का आरोप

(जीएनएस)। जयपुर। देशभर में निवेश के नाम पर लोगों को बड़े मुनाफे का सपना दिखाकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले डिजी मुद्रा नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा प्रहार किया है। ईडी के जयपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मेसर्स डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक प्रकाश चंद जैन को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार 27 जनवरी को हुई इस कार्रवाई के बाद प्रकाश जैन को जयपुर स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें चार दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों की विस्तृत जांच के बाद की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित एसटीएफ सहित राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि प्रकाश चंद जैन, रवि जैन और उनके अन्य सहयोगियों ने आपस में मिलीभगत कर एक संगठित नेटवर्क के जरिए हजारों निवेशकों को झूठी और आकर्षक निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए उकसाया।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने निवेशकों को असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का लालच देकर बड़ी रकम जुटाई। शुरुआती दौर में कुछ निवेशकों को लाभ देकर भरोसा जीता गया और इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों से करोड़ों रुपये इकट्ठा किए गए। पीएमएलए के तहत अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से एकत्र की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के वास्तविक व्यावसायिक उपयोग में लगाने के बजाय प्रमोटरों, निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों तथा एजेंटों के निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

ईडी का कहना है कि अपराध से अर्जित इस धन का इस्तेमाल आरोपियों ने अपने और अपने परिजनों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया। जमीन, मकान और अन्य रियल एस्टेट निवेश के जरिए अवैध कमाई को वैध दिखाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी को ऐसे कई दस्तावेज और लेन-देन के सबूत मिले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि करते हैं।

इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों से जुड़े कुल सात ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 11.3 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। तलाशी के दौरान विभिन्न अचल संपत्तियों और संस्थाओं से जुड़े कई बैंक खातों का भी पता चला, जिनमें करीब 38 लाख रुपये की राशि जमा होने की जानकारी सामने आई। जांच में एक और अहम खुलासा यह भी हुआ है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक रवि जैन फिलहाल दुबई में रह रहा है। ईडी के मुताबिक, रवि जैन ने अपराध से प्राप्त धन का एक हिस्सा विदेश भेजकर दुबई में रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश किया है।

भारत- ईयू एफटीए, माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप में एक बड़ी कामयाबी; निर्यात प्रतिस्पर्धा को बदलने और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के एकीकरण को गहरा करने के लिए तैयार: फियो अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन

(जीएनएस)। नई दिल्ली; 27 जनवरी, 2026ः फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) ने भारत-यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता (भारत- ईयू एफटीए) के ऐतिहासिक ऐलान के बाद, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की दूर की सोच वाली लीडरशिप, दूर की स्ट्रेटेजिक सोच और फैसले लेने वाली डिप्लोमेसी की दिल से तारीफ़ की है। इस ऐतिहासिक समझौते का ऐलान आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नई दिल्ली में हुए 16वें भारत- ईयू समिट में मिलकर किया। भारत - ईयू एफटीए का पूरा होना भारत की वैश्विक इकोनॉमिक यात्रा में एक अहम पड़ाव है और यह व्यापार से होने वाली ग्रोथ, इकोनॉमिक सुधारों और वैश्विक एकीकरण के लिए भारत सरकार के पक्के प्रतिबद्धता का सबूत है। यह समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन को भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर मज़बूत करता है, जो खुले बाज़ार, पहले से तय और सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध हैं। फियो अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह 2022 में बातचीत फिर से शुरू होने के बाद से सरकार के मज़बूत राजनीतिक इरादे के साथ लगातार, नतीजे पर आधारित बातचीत का नतीजा है, जो एक संतुलित, मॉडर्न और नियमों पर आधारित इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाने के साझा नज़रिए को दिखाता है।

यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। वित्त वर्ष 2024–25 में, भारत - ईयू का वस्तु का आपसी व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये (136.54 बिलियन डॉलर) था, जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये (75.85 बिलियन डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये (60.68 बिलियन डॉलर) का इंपोर्ट शामिल था। सेवा क्षेत्र में व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये (83.10 बिलियन डॉलर) तक पहुँच गया। भारत और ईयू मिलकर दुनिया की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा हैं—यह एक ऐसा अवसर है जिसे भारत सरकार ने इस बदलाव लाने वाले एग्रीमेंट के ज़रिए स्ट्रेटेजिक तरीके से खोला है।

श्री रल्हन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के डायनैमिक और रिफॉर्म-ओरिएंटेड लीडरशिप में भारत- ईयू एफटीए का सफल होना एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ाएगा और वैश्विक वैल्यू चेन के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देगा। यह एग्रीमेंट भारतीय निर्यातकों के लिए वस्तु और सेवा क्षेत्र में, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स, एमएसएमई, महिला एंटरप्रेन्योर्स, कारीगरों और युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए पहले कभी नहीं देखा गया मार्केट एक्सेस खोलता है—जो सरकार के इनक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा के मुख्य फोकस एरिया हैं।

उन्होंने कहा कि लगभग 33 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होने से, एफटीए टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर, फुटवियर, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, मरीन प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल जैसे खास सेक्टर को तुरंत और ठोस फायदा देगा। इन फायदों से ज़्यादा निर्यात, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और वैश्विक व्यापार में जमीनी स्तर पर मजबूत भागीदारी होगी, जिससे निर्यात से होने वाली खुशहाली के सरकार के विजन को मजबूती मिलेगी।

इस समझौते में वस्तु और सेवा क्षेत्र का व्यापार, ओरिजिन के नियम, कस्टम में आसानी, व्यापार उपचारों और डिजिटल व्यापार और एमएसएमई जैसे उभरते हुए सेक्टर पूरी तरह से शामिल हैं। इसमें नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत सिस्टम शामिल हैं – जो बेहतर रेगुलेटरी सहयोग, ट्रांसपेरेंट एसपीएस उपायों और आसान कस्टम प्रोसेस के ज़रिए ईयू रेगुलेटर्स के साथ सरकार के प्रोएक्टिव जुड़ाव का नतीजा है । ऑटोमोबाइल सेक्टर में सोच-समझकर और कोटा- आधारित लिबरलाइजेशन से ईयू मैन्युफैक्चरर्स को भारत में एडवांस्ड मॉडल पेश करने की इजाज़त मिलेगी, साथ ही सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ जुड़े भविष्य के मौके भी बनेंगे।

भारतीय उपभोक्ताओं को हाई-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तक बेहतर एक्सेस और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से फायदा होने की उम्मीद है। चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस के साथ एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा, जबकि सरकार ने डेयरी और अनाज जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को समझदारी से सुरक्षित रखा है, जिससे किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।

एफटीए आईटी/आईटीईएस , प्रोफेशनल सर्विसेज़, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज़, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और दूसरी बिजनेस सर्विसेज़ सहित सर्विसेज़ में कमर्शियली सार्थक प्रतिबद्धता देता है। 144 ईयू सब-सेक्टर्स में अनुमानित मार्केट एक्सेस भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अवसरों को काफी बढ़ाएगा, जबकि रेसिप्रोकल एक्सेस भारत में हाई-टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। प्रोग्रेसिव मोबिलिटी प्रोविजन्स भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वैश्विक अवसरों को प्राप्त करने के लिए सरकार की लगातार कोशिशों को दिखाते हैं, जिसमें शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रैवल, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस सप्लायर्स, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स और डिपेंडेंट्स के लिए काम के अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर्स को ईयू सदस्य देशों में अपने टाइटल के तहत काम करने की मान्यता दिलाई है, जहाँ ऐसे तरीकों को रेगुलेट नहीं किया जाता है - यह एक महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह समझौता टीआरआईपीएस के तहत बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूत करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को मान्यता देता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें सीबीएएम कंप्लायंस से संबंधित सहायता भी शामिल है।

श्री रल्हन ने दोहराया कि भारत- ईयू एफटीए, सरकार के हाल ही में ब्रिटेन और ईएफटीए के साथ हुए एफटीए के साथ मिलकर, भारतीय निर्यातकों के लिए पूरे यूरोपीय बाजार को प्रभावी ढंग से खोलता है, जो भारत की व्यापार कूटनीति में एक रणनीतिक सफलता है। यह ऐतिहासिक समझौता 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, और भारत को एक लचीले, प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी वैश्विक व्यापार नेता के रूप में स्थापित करता है।

भारत- ईयू एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव में एक नए युग की शुरुआत करता है, जो भारत सरकार की रणनीतिक स्पष्टता, बातचीत की ताकत और दीर्घकालिक विजन को दर्शाता है - 27-सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है, साथ ही भविष्य की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नींव रखता है।

शेयर बाजार में दस्तक देने उतरी कनिष्क अल्युमिनियम, 29 .20 करोड़ रुपये का आईपीओ निवेशकों के लिए खुला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अल्युमिनियम उत्पादों के निर्माण से जुड़ी कंपनी कनिष्क अल्युमिनियम इंडिया लिमिटेड ने शेयर बाजार में कदम रखते हुए अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दिया है। कंपनी का यह आईपीओ कुल 29.20 करोड़ रुपये का है, जिसमें निवेशक 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बाजार में इस इश्यू को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, खासकर उन निवेशकों के बीच जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उभरती कंपनियों में निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत प्रति शेयर 73 रुपये का इश्यू प्राइस तय किया है। इसमें कुल 40 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिनका फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। निवेशकों को कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा, जिसमें 1,600 शेयर शामिल हैं। इस तरह एक लॉट में निवेश की राशि 1,16,800 रुपये बैठती है। रिटेल निवेशकों को अधिकतम दो लॉट तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है, यानी उन्हें कुल 2,33,600 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ की संरचना की बात करें तो इसमें रिटेल निवेशकों के लिए 47.52 प्रतिशत हिस्सेदारी आरक्षित की गई है, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए 47.48 प्रतिशत शेयर रखे गए हैं। इसके अलावा 5 प्रतिशत हिस्सा मार्केट मेकर्स के लिए सुरक्षित किया गया है। इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर की भूमिका सन कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड निभा रही है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। सनफ्लावर ब्रोकिंग इस इश्यू में मार्केट मेकर के तौर पर काम कर रही है।

आईपीओ की प्रक्रिया के अनुसार, 2 फरवरी को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा और 3 फरवरी से सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके बाद कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग तय समय पर स्टॉक एक्सचेंज पर होने की उम्मीद है। बाजार जानकारों का मानना है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की विस्तार योजनाएं निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कनिष्क अल्युमिनियम इंडिया लिमिटेड ने बीते कुछ वर्षों में अपने कारोबार को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाया है। हालांकि शुद्ध लाभ में कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन हालिया आंकड़े कंपनी की बेहतर होती सेहत की ओर इशारा करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का शुद्ध लाभ 1.76 करोड़ रुपये रहा था, जो 2023-24 में घटकर 1.52 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद 2024-25 में कंपनी ने जोरदार वापसी करते हुए 3.04 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही, यानी अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच ही कंपनी 2.15 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा चुकी है, जो इसके मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दर्शाता है।

कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में भी लगातार वृद्धि देखी गई है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। 2022-23 में जहां रिजर्व और सरप्लस 1.11 करोड़ रुपये था, वहीं 2025 की पहली छमाही तक यह बढ़कर 9.28 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही EBITDA में भी सुधार देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 में EBITDA 4.06 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 6.63 करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह आंकड़ा 4.08 करोड़ रुपये रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए कर सकती है।

उत्तराखंड में विकास और हरित ऊर्जा को नई रफ्तार, कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति सहित आठ अहम फैसलों पर लगाई मुहर

(जीएनएस)। देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 'उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति–2026' समेत कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को राज्य के दीर्घकालिक विकास, निवेश आकर्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

मंत्रिमंडल बैठक की शुरुआत शोक संवेदना के साथ हुई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और हाल ही में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कैबिनेट ने दो मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है और अजित पवार का सार्वजनिक जीवन समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई हाइड्रोजन नीति को मंजूरी देना रहा। सरकार का मानना है कि इस नीति से उत्तराखंड को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नीति के तहत प्रोत्साहन, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं से जुड़े निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि प्रक्रिया सरल और प्रभावी रहे। कैबिनेट ने सामरिक और नागरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक और बड़ा फैसला लेते हुए उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ और चमोली के गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। इससे सीमावर्ती और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत होगी और सेना के साथ-साथ आम नागरिकों को भी बेहतर हवाई सुविधा मिल सकेगी।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने सेवाकाल में एक बार आपसी सहमति से स्थानांतरण की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। लंबे समय से कर्मचारियों की यह मांग थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए आपसी सहमति से सीधे भूमि क्रय का अधिकार भी सरकार ने प्रदान किया है। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होने और विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में भी कैबिनेट ने कदम बढ़ाया है। बैठक में चार नए जनजाति कल्याण अधिकारी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई, जिससे दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। वहीं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उधमसिंहनगर जिले में स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि सिडकुल को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इसके अलावा औद्योगिक पट्टों से संबंधित नियमावली में संशोधन कर उप-पट्टे की व्यवस्था को सरल बनाया गया है, ताकि निवेशकों को अधिक सहूलियत मिल सके। भूजल के व्यावसायिक उपयोग से जुड़े नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिससे संसाधनों का संतुलित और नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जीआरडी उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा के नए अवसर राज्य में उपलब्ध होंगे।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट बैठक के फैसलों को उत्तराखंड के लिए विकास, निवेश, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों का संतुलित रोडमैप माना जा रहा है।

सोना वायदा में 6000 रुपये और चांदी वायदा में 20456 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा 52 रुपये बढ़ा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 237851.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 88522.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 149323.3 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 46600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3908.54 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 77878.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 159900 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 164900 रुपये और नीचे में 159900 रुपये पर पहुंचकर, 157699 रुपये के पिछले बंद के सामने 6000 रुपये या 3.8 फीसदी बढ़कर 163699 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 2036 रुपये या 1.5 फीसदी की तेजी के संग 137689 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 287 रुपये या 1.69 फीसदी की तेजी के संग 17248 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी फरवरी वायदा 159296 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 164748 रुपये और नीचे में 159296 रुपये पर पहुंचकर, 5349 रुपये या 3.37 फीसदी की तेजी के संग 164093 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 167099 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 170500 रुपये और नीचे में 167099 रुपये पर पहुंचकर, 166335 रुपये के पिछले बंद के सामने 3512 रुपये या 2.11 फीसदी की तेजी के संग 169847 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 364821 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 383100 रुपये और नीचे में 364821 रुपये पर पहुंचकर, 356279 रुपये के पिछले बंद के सामने 20456 रुपये या 5.74 फीसदी बढ़कर 376735 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 20594 रुपये या 5.69 फीसदी की मजबूती के साथ 382777 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 20600 रुपये या 5.69 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 382772 रुपये प्रति किलो पर आ गया। मेटल वर्ग में 6194.00 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 14.65 रुपये या 1.12 फीसदी की तेजी के संग 1322.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि जस्ता फरवरी वायदा रु.9.9 या 3.05 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 334.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 5.1 रुपये या 1.6 फीसदी की मजबूती के साथ 323.8 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 30 पैसे या 0.16 फीसदी चढ़कर 191.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3907.74 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5755 रुपये के भाव पर खूलकर, 5797 रुपये के दिन के उच्च और 5713 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 52 रुपये या 0.91 फीसदी की मजबूती के साथ 5757 रुपये प्रति बैरल बोला गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 57 रुपये या 1 फीसदी बढ़कर 5761 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 350.3 रुपये क भाव पर खूलकर, 350.3 रुपये के दिन के उच्च और 329.1 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 352.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 16 रुपये या 4.53 फीसदी की गिरावट के साथ 336.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 15.8 रुपये या 4.48 फीसदी घटकर 337 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 88522.86 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 149323.3 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 77878.03 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 46600 पॉइंट के स्तर पर

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1022 रुपये के भाव पर खूलकर, 1.4 रुपये या 0.14 फीसदी की मजबूती के साथ 1009.9 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 48407.75 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 29470.28 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4867.56 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 625.93 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 30.34 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 670.17 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 788.21 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3104.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19666 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 103755 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 38760 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 404235 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 71047 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14317 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 35743 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 98610 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21148 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 22460 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 45500 पॉइंट पर खूलकर, 46800 के उच्च और 45500 के नीचले स्तर को छूकर, 1642 पॉइंट बढ़कर 46600 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 37.4 रुपये की बढ़त के साथ 268.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 7.85 रुपये की गिरावट के साथ 33.55 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2529.5 रुपये की बढ़त के साथ 8733.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 330000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 11964 रुपये की बढ़त के साथ 62900 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.38 रुपये की बढ़त के साथ 35.11 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.82 रुपये की बढ़त के साथ 19.45 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 23.5 रुपये की गिरावट के साथ 246.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5.3 रुपये की बढ़त के साथ 17.15 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 482.5 रुपये की गिरावट के साथ 1222 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4972.5 रुपये की गिरावट के साथ 8500 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.6 रुपये की गिरावट के साथ 16.08 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 10 पैसे के सुधार के साथ 5.05 रुपये हुआ।